



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 1984/भाद्र 14, 1906

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 1984/BHADRA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1984

फा० सं० 8/3/84-इष्टमू. टी. :—ऊन तथा ऊनी उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था और जून 1983 में प्राप्त उसकी रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है। भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कारगर तथा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक अस्त:संज्ञालय अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

2. इस अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे।

(1) ऊन तथा ऊनी उद्योगों के अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार करना और सरकार की ओर से समिति के निर्णय बनाना।

(2) उस विभाग/अधिकरण का अभिज्ञात करना जिसको निश्चित समय में सिफारिश (सिफारिशें) कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

3. अधिकार प्राप्त समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. सचिव, वस्त्र विभाग

अध्यक्ष

2. सचिव, व्यवसाय विभाग

सदस्य

3. सचिव, राजस्व विभाग

सदस्य

4. सचिव, भारी उद्योग विभाग

सदस्य

5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग

सदस्य

6. सचिव, कृषि विभाग (पशुपालन प्रभाग)

सदस्य

7. सचिव, श्रम विभाग

सदस्य

8. मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात

सदस्य

9. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार,
वाणिज्य मंत्रालय

सदस्य

10. अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
(वैकिंग प्रभाग)

सदस्य

11. वस्त्र आयुक्त, बम्बई

सदस्य

12. वस्त्र विभाग में ऊनी वस्त्र से
सम्बन्धित संयुक्त सचिव

संयोजक-सदस्य

समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार और भी सदस्य शामिल कर सकेंगे।

4. आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति वस्त्र विभाग, वाणिज्य मंत्रालय को उचित रूप से अनुदेश देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th September, 1984

F.No. 8/3/84-WT:— A Study Group was constituted to study the problems of Wool and Woollen Industry and its Report received in June, 1983, has been examined. The Government of India have decided to appoint an inter-ministerial "Empowered Committee" for effecting and expeditious implementation of the recommendations made in the said Report.

2. The terms of reference of the Empowered Committee will be as under :

- (i) To consider the recommendations of the Study Group of Wool and Woollen Industry and indicate the decisions of the Committee on behalf of the Government.
- (ii) To identify the Department/Agency which would be entrusted with responsibility of implementing the recommendation (s) in a time-bound frame.

3. The Empowered Committee will consist of the following :

1. Secretary Deptt. of Textiles—Chairman.
2. Secretary, Deptt. of Expenditure —Member.
3. Secretary, Deptt. of Revenue —Member.
4. Secretary, Deptt. of Heavy Industries—Member.

5. Secretary, Deptt. of Industrial Development—Member.
6. Secretary, Deptt. of Agriculture—Member.
(Animal Husbandry Division).
7. Secretary, Deptt. of Labour—Member
8. Chief Controller of Imports & Exports—Member
9. Additional Secretary and Financial Adviser—
Member. Ministry of Commerce.
10. Additional Secretary, Deptt. of Economic Affairs
—Member.
(Banking Division).
11. Textile Commissioner. Bombay—Member.
12. Joint Secretary dealing with Woollen Textiles in the
Deptt. of Textiles, Convener—Member.

Chairman of the Committee could co-opt further members, if necessary.

4. The Empowered Committee shall suitably instruct the Department of Textiles, Ministry of Commerce, to obtain the approval of Cabinet Committee on Economic Affairs wherever called for.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. K. BAGCHI, Jr. Secy.